

दादरी में बनेगा लॉजिस्टिक पार्क 15000 लोगों को मिलेगा रोजगार

ग्रेनो प्राधिकरण के बोर्ड से मंजूरी मिलने के छह दिन बाद परियोजना लॉन्च की गई

शशांक मिश्र

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण ने पाली और मकौड़ा गांव के सेक्टर कम्पा-2, दादरी में 174 एकड़ में फैले मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमपीएल) के लिए भूखंड आवंटन की योजना लॉन्च की है। इस परियोजना को 17 मई को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मंजूरी मिली थी। प्राधिकरण के सबसे न्यूनतम दर 11 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर पर इसका आवंटन किया जाएगा। यह लॉजिस्टिक्स पार्क रोजगार और निवेश के लिहाज से पूरे एनसीआर के विकास का नया केंद्र बनकर उभरेगा।

लॉजिस्टिक पार्क नोएडा एयरपोर्ट, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सीधे जुड़ा होगा। यह पार्क 250 एकड़ के इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीटी) से सटा होगा। दोनों मिलकर दादरी क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सबसे बड़ा कार्गो हैंडलिंग जोन बनाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना न केवल लगभग पांच हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करेगी, 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। प्राधिकरण की योजना है कि यह पार्क आधुनिक सुविधाओं जैसे कार्गो यार्ड, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर टर्मिनल, डिजिटल

रिकॉर्ड समय में निर्णय और क्रियान्वयन

फरवरी 2025 में मास्टर प्लान-2041 के तहत दादरी क्षेत्र के भूमि उपयोग में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई। 17 मई को बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिली और 23 मई को योजना लॉन्च कर दी गई। प्राधिकरण के अधिकारी इस लॉजिस्टिक पार्क के लिए

भूखंड आवंटन प्रक्रिया को अब तक की सबसे तेज कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। हालांकि 17 मई को हुई बोर्ड बैठक में इस योजना मंजूरी और पाली-मकौड़ा गांव के भू-उपयोग बदलाव की पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक नहीं किया गया है।

सेक्टर कम्पा-2 के भू-उपयोग में किया गया है बदलाव

न्यूनतम दर 11 हजार प्रति वर्ग मीटर पर होगा जमीन का आवंटन

उत्तर भारत के लिए गेमचेंजर होगी योजना

“यह योजना लॉजिस्टिक्स सेक्टर में उत्तर भारत के लिए गेमचेंजर साबित होगी। एयरपोर्ट, रेल और रोड से जुड़ाव होने से पार्क निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। -एनके सिंह, ओएसडी, ग्रेनो प्राधिकरण

परियोजना की योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

इस पार्क में भूमि आवंटन के लिए कंपनियों को कम से कम 1,200 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव देना होगा, जिसमें भूमि लागत शामिल नहीं है। आवेदकों के पास कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, विशेष रूप से आईसीटी या रेल टर्मिनल संचालन में। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और आवंटन स्क्रीनिंग कमेटी व आवंटन समिति द्वारा अंक आधारित प्रणाली से तय किया जाएगा।

लॉजिस्टिक हैंडलिंग और स्किल डिवेलपमेंट सेंटर से लैस हो।

गौरतलब है कि दादरी में ही 825 एकड़ में दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) के अंतर्गत मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) विकसित किया जा रहा है। 8,325 करोड़

रुपये की लागत से तैयार हो रही इस परियोजना का निर्माण कार्य अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। यह पीपीपी मॉडल के तहत विकसित होगी, जिसमें 5,911 करोड़ रुपये का निवेश प्राइवेट कंपनियों द्वारा डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल पर किया जाएगा।